दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin
बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-३०९ वा | मंगळवार १० जून २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

मुंबई लोकल ट्रेन हादसा: ८ यात्रियों की दर्दनाक मौत, राजकीय प्रतिक्रियाओं में सुरक्षा, जवाबदेही और व्यवस्था पर सवाल

स्थान: मुंबई । दिनांक: ९ जून २०२५ । विशेष रिपोर्ट, जमीर काजी

मुंबई की जीवनरेखा मानी जाने वाली लोकल ट्रेन में एक बार फिर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दिवा और मुंब्रा स्टेशन के बीच सोमवार सुबह हुए हादसे में ८ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा उस समय हुआ जब लोकल ट्रेन में भीषण भीड़ के कारण यात्री दरवाजे से लटकते हुए यात्रा कर रहे थे और संतुलन बिगड़ने के कारण ट्रेन से नीचे गिर गए।

प्रशासन और राजकीय नेतृत्व की प्रतिक्रियाएं:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस:

यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। घायलों को शिवाजी हॉस्पिटल और ठाणे सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे विभाग ने जांच शुरू कर दी है ताकि इस दुर्घटना के कारणों का जल्द पता चल सके।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे:

मुंब्रा स्टेशन के पास हुई दुर्घटना बेहद दुखद है। रोजाना हजारों यात्री इस मार्ग पर यात्रा करते हैं। रेलवे विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है, और जल्द ही असली वजह सामने आएगी।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार:

यह घटना उपनगरीय रेलवे की भीड़ और सुरक्षा की उपेक्षा का नतीजा है। रेलवे को प्रभावी और सुरक्षित बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

राकांपा नेता शरद पवार:

मध्य रेलवे पर प्रतिदिन औसतन ६ से ७ यात्रियों की मृत्यु होती है, यह बेहद गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। रेलवे हादसे के बाद यात्रियों को ही दोषी ठहराना सरासर गलत है। बढ़ती भीड़ और ट्रेन सेवाओं की कमी इसके लिए जिम्मेदार है। रेलवे मंत्रालय को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए, लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक दरवाजों की त्वरित स्थापना होनी चाहिए।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ:

यह हादसा एक दुर्घटना नहीं, बल्कि भाजपा सरकार की निष्क्रियता का परिणाम है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को तुरंत हटाया जाना चाहिए। पिछले ११ वर्षों से मुंबई के लोगों को सिर्फ झूठे वादे और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। टेंडर-आधारित कमिशन संस्कृति ने आम आदमी की जान को खतरे में डाल दिया है।

मनसे प्रमुख राज ठाकरे:

मुंबई में ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। रेलवे के लिए अलग महामंडल की मांग वर्षों से की जा रही है लेकिन किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। शहरों की प्लानिंग पूरी तरह से चरमरा गई है। सब कुछ सिर्फ चुनाव और प्रचार तक सीमित है। क्या मीडिया इन मुद्दों पर सवाल उठाएगी? विदेशों में ऐसी घटना होती तो पूरी व्यवस्था हिल जाती, लेकिन यहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं।

मुंबई लोकल हादसे अब महज दुर्घटनाएं नहीं, बल्कि व्यवस्थागत विफलता और शासन की उदासीनता के प्रतीक बन चुके हैं। एक ओर रेलवे प्रशासन ऑटोमेटिक दरवाजों और भीड़ नियंत्रण जैसे उपायों को लेकर सुस्त है, वहीं दूसरी ओर राज्य व केंद्र सरकारें जिम्मेदारी टालने में व्यस्त हैं।

हर वर्ष बजट में बुलेट ट्रेन, मेट्रो विस्तार, स्मार्ट स्टेशन जैसी घोषणाएं होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में मुंबई लोकल के हजारों यात्री रोज जान हथेली पर रखकर यात्रा कर रहे हैं।

इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं -

क्या रेल मंत्रालय यात्रियों की जिंदगी को प्राथमिकता देगा?

क्या भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा उपाय केवल कागजों तक सीमित रहेंगे?

क्या मुंबई की जनता को सुरक्षित यात्रा का अधिकार मिलेगा या हादसों की राजनीति ही चलती रहेगी?

सरकार को चाहिए कि वह हादसों की कीमत पर नहीं, यात्रियों की जान की हिफाजत के आधार पर योजनाएं बनाए। वरना हर मौत एक राजनीतिक श्रद्धांजलि बनकर रह जाएगी - और सुध नहीं आएगी।

डॉ.योगेश क्षीरसागरने लिया पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा का दर्शन

स्थान: बीड़, दिनांक ९ (प्रतिनिधि)

बीड़ तालुका के चाकरवाडी गांव में आयोजित अखंड हरिनाम सप्ताह के अंतर्गत प्रसिद्ध कथा वाचक पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा की शिवपुराण कथा का शुभारंभ उत्साहपूर्वक हुआ। यह आयोजन २०वीं शताब्दी के महान संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली महाराज के रौप्य महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया है। कथा के दूसरे दिन सोमवार (दिनांक ९) को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता डॉ. योगेश क्षीरसागर ने पंडित प्रदीप मिश्रा का दर्शन किया और कथा श्रवण की।

कथा की शुरुआत ह.भ.प. महादेव महाराज चाकरवाडीकर की उपस्थिति में विधिवत पूजा के साथ हुई। डॉ. योगेश क्षीरसागर ने भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर कथा में भाग लिया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा नेता नंदकिशोर मुंदड़ा, डॉ. दीपाताई क्षीरसागर, संतोष सोहनी, शुभम धूत समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हरिनाम सप्ताह के अवसर पर भक्तों में गहरा भक्तिभाव देखा जा रहा है और पूरे परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण व्याप्त है।

मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर पुलिस की नई गाइडलाइंस को मुस्लिम संगठनों की चुनौती, हाईकोर्ट में जाएगी याचिका

मुंबई, दिनांक ९ जून । प्रतिनिधि विशेष

महाराष्ट्र सरकार की ओर से हाल ही में मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (-ॠध्झ) द्वारा जारी नए एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) को लेकर राज्य के मुस्लिम संगठनों ने तीखी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह निर्देश असंवैधानिक, अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ और धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन है। इस फैसले के खिलाफ अब मुंबई हाईकोर्ट में संयुक्त याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है।

यह निर्णय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान की अध्यक्षता में मुंबई के साकीनाका इलाके में आयोजित एक बैठक में लिया गया, जिसमें कई धार्मिक व सामाजिक संगठनों के प्रमुख, प्रसिद्ध उलेमा, कानूनविद और समाजसेवी मौजूद थे।

इस बैठक में मौलाना हलीमुल्लाह खान कासमी (अध्यक्ष, जमीयत उलमा महाराष्ट्र), मौलाना अब्दुस्सलाम सलफी (अध्यक्ष, जमीयत अहले हदीस मुंबई) और अन्य प्रतिनिधियों ने पुलिस के इस निर्देश पर गंभीर चिंता जताई। उनका कहना था कि यह न केवल धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि यह विभिन्न न्यायालयों के पूर्व के निर्णयों के भी खिलाफ है। नसीम खान का बयान: यह एसओपी

पूरी तरह असंवैधानिक नसीम खान ने अपने संबोधन में कहा कि -ॠध्झ द्वारा जारी यह निर्देश पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने पुराने आदेशों में सिर्फ ध्वनि प्रदूषण की सीमा तय करने की बात कही थी, लेकिन नई एसओपी में मस्जिदों से मालिकाना हक, स्थल की जानकारी और नगर निगम की अनुमति की मांग की जा रही है - जो कि न तो शरई तौर पर स्वीकार्य है, न ही संविधान के तहत। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस यह कार्रवाई किसी विशेष राजनीतिक दबाव में कर रही है और यह एक सुनियोजित भेदभाव का हिस्सा है। उन्होंने घोषणा की कि वरिष्ठ वकील एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ मछाला की कानूनी सलाह के तहत मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी, और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा।मुस्लिम नेताओं का आह्वान: एकता और कानूनी संघर्ष की जरूरतमौलाना हलीमुल्लाह खान ने अपने संबोधन में मुस्लिम समुदाय से एकजुटता की अपील करते हुए कहा कि अज़ान, नमाज़ और इस्लामी प्रतीकों की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी विचारधाराओं को एक मंच पर आने का आह्वान किया। मौलाना अब्दुस्सलाम सलफी ने कहा कि मौजूदा हालात उम्मत-ए-मुस्लिम के लिए एक इम्तिहान हैं, और इस समय धैर्य, एकजुटता और ईमानदारी से काम लेने की आवश्यकता है।वकीलों की राय: एसओपी न्यायालय के आदेशों के खिलाफ एडवोकेट करीम पठान और अलम खान ने कानूनी विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए बताया कि पुलिस का यह नया सर्कुलर न्यायालयों के पुराने फैसलों से मेल नहीं खाता और इसे कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं माना जा सकता।

अन्य प्रतिनिधियों के विचार और समापन बैठक में अल्हाज मोहम्मद वसीम हसन, मौलाना आतिफ सानाबली, अहसान राईन, सैयद अरसलान और अन्य वक्ताओं ने भी इस कार्रवाई की सामूहिक निंदा की और संयुक्त कानूनी कार्रवाई की पूर्ण समर्थन किया। बैठक का समापन मौलाना निज़ामुद्दीन अशरफी की दुआ पर हुआ, जिसमें देश में शांति, न्याय और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रार्थना की गई। प्रेस से बातचीत में नसीम खान का आरोप: भाजपा सरकार ने मुस्लिम विरोधी मोर्चा खोला बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नसीम खान ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने मुस्लिमों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम पर सुनियोजित हमले हो रहे हैं, और अब समय आ गया है कि हम कानूनी और संवैधानिक रास्ते से अपनी आवाज बुलंद करें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस सर्कुलर को वापस नहीं लेती, तो मुकदमेबाज़ी तेज़ की जाएगी। विशेष टिप्पणी: यह मामला महज़ लाउडस्पीकर की आवाज़ का नहीं, बल्कि धार्मिक आज़ादी, अल्पसंख्यक अधिकार और संविधान की गरिमा से जुड़ा है। अगर ध्वनि सीमा की आड़ में किसी एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, तो यह सांविधानिक समानता के खिलाफ है। मुस्लिम संगठनों की ओर से इस मामले को न्यायिक चुनौती देना न केवल वाजिब है, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती के लिए भी ज़रूरी है।

देश की अर्थव्यवस्था को संवारने वालों को ही बनाया जा रहा है बलि का बकरा: विश्वास उतगी

आरबीआई की रेपो रेट में कटौती से बड़े पूंजीपतियों को फायदा, बचतकर्ता और पेंशनधारी बन रहे हैं शिकार

रिपोर्ट: मुंबई से । दिनांक: ९ जून २०२५

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बैंकिंग मामलों के विशेषज्ञ विश्वास उतगी ने सोमवार को मुंबई स्थित गांधी भवन में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (ठइख) की हालिया मौद्रिक नीति की तीखी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि रेपो रेट में ०.५% की कटौती दरअसल बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को राहत देने की सोची-समझी चाल है, जिसका खामियाजा देश के करोड़ों आम बचतकर्ताओं, पेंशनधारियों, वरिष्ठ नागरिकों और मेहनतकश लोगों को भुगतना पड़ेगा।

आरबीआई के फैसलों पर विश्वास उतगी का आरोप:

उतगी ने कहा कि जब देश की ऋध्झ वृद्धि दर ६.५% और मुद्रास्फीति ४% से नीचे है, तब नीतिगत नरमी का यह फैसला अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से अनावश्यक और संदिग्ध है।

उन्होंने बताया कि रेपो रेट को ६% से घटाकर ५.५% कर दिया गया है, जिससे बैंकों के कर्ज सस्ते तो हो सकते हैं, लेकिन बचत खातों, फिक्स्ड डिपॉज़िट्स और पेंशन पर मिलने वाले ब्याज में कटौती हो जाएगी, जिससे आमजन प्रभावित होगा।

बचतकर्ता सबसे बड़ा नुकसान सहने वाले:

उतगी ने चेतावनी दी कि रिज़र्व बैंक द्वारा उठठ (कैश रिज़र्व रेशियो) को दिसंबर २०२५ तक ४% से घटाकर ३% करने का फैसला २.५ लाख करोड़ की अतिरिक्त तरलता पैदा करेगा, जो अगर सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को दिए गए सस्ते कर्ज में बदल गई तो इसका फायदा आम लोगों को नहीं मिलेगा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा धन को भले ही 'सुरक्षित' कहा जाता है, लेकिन जब ब्याज दरें मुद्रास्फीति से भी कम हो जाती हैं, तो असल में लोगों की जमा पूंजी अपनी 'वास्तविक कीमत' खो देती है।

देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिक और रिटायर्ड कर्मचारी मासिक खर्चा सिर्फ बैंक ब्याज से चलाते हैं, और जब वही ब्याज कम होता है तो उनकी जिंदगी संकट में आ जाती है।

₹ड ब्याज दरों में गिरावट का खुला डेटा:

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: ७.५% से घटकर ६.८५%

बैंक ऑफ महाराष्ट्र: ७.१५% से ६.५%

फेडरल बैंक: ७.५% से ७%

इंडसइंड बैंक: ७.२५% से ७%

उतगी ने कहा कि ये आंकड़े साबित करते हैं कि बचत पर मिलने वाला रिटर्न लगातार घट रहा है।

बचत और डिपॉज़िट का राष्ट्रीय परिदृश्य:

मार्च २०२५ तक देश में कुल बैंक डिपॉज़िट की रकम २३४.५ लाख करोड़ तक पहुँच चुकी है -

मेट्रो शहरों से २४.८ लाख करोड़

शहरी क्षेत्रों से ४९ लाख करोड़

अर्धशहरी इलाकों से ३६.२ लाख करोड़

ग्रामीण क्षेत्रों से २४.४ लाख करोड़

इसमें से:

सेविंग अकाउंट्स में ५९.७ लाख करोड़

करंट अकाउंट्स में १८.५ लाख करोड़

फिक्स्ड डिपॉज़िट्स में १०३ लाख करोड़

इसके बावजूद, सालाना जमा दर केवल ७% रही, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि लोग अब बचत से बच रहे हैं क्योंकि उस पर उन्हें पर्याप्त रिटर्न नहीं मिल रहा।

कर्ज माफी और दोहरे मापदंड पर सवाल:

उतगी ने सवाल किया कि वो बड़े उद्योगपति जिन्होंने करोड़ों का कर्ज लिया और फिर देश छोड़कर भाग गए, या जिन्हें राइट-ऑफ कर दिया गया - उनका हिसाब कौन देगा?

उन्होंने कहा कि जब आम आदमी एक ईएमआई चुकाने में चूक करता है तो बैंक तुरंत जुर्माना लगाते हैं, जबकि उद्योगपतियों को 'व्यापारिक विवशता' के नाम पर राहत दी जाती है।

विश्वास उतगी के तीन तीखे सवाल:

१. बचतकर्ताओं और छोटे निवेशकों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा?

२. सरकार और बैंक सिर्फ अमीर कर्जदारों के लिए ही क्यों सक्रिय रहते हैं?

३. देश में निजी निवेश और रोजगार के अवसर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं?

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर यह उजागर किया है कि नीतिगत घोषणाओं के पीछे आम आदमी सबसे कमजोर कड़ी बनकर रह गया है।

जहाँ बड़े कारोबारियों को कर्ज और छूट मिलती है, वहीं देश के मेहनतकश नागरिकों की जीवनभर की बचत धीरे-धीरे खत्म की जा रही है - बिना किसी राजनीतिक शर्मिंदगी या जवाबदेही के।

अगर देश की अर्थव्यवस्था बचानी है, तो पहले उन लोगों की रक्षा करनी होगी, जिनकी बचत पर यह अर्थव्यवस्था टिकी है।

क्योंकि अगर यही कंधे दबा दिए गए, तो अर्थव्यवस्था का बोझ संभालने वाला कोई नहीं बचेगा।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वो साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

एसएफआई के राज्य अध्यक्ष पद पर रोहिदास जाधव, सचिव पद पर सोमनाथ निर्मल की नियुक्ति

स्थान: बीड़ (प्रतिनिधि), दिनांक ९

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) का १९वां महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर में बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। यह तीन दिवसीय अधिवेशन २ से ४ जून २०२५ के बीच आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के सभी जिलों से छात्र प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन में नई राज्य कमेटी का गठन किया गया, जिसमें बीड जिले के रोहिदास जाधव को एसएफआई के राज्य अध्यक्ष तथा सोमनाथ निर्मल को राज्य सचिव पद पर सर्वसम्मति से चुना गया।

इस अधिवेशन में ४५ सदस्यीय राज्य समिति का भी चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। इसमें बीड़ जिले के एसएफआई जिलाध्यक्ष सत्यजित मस्के को राज्य उपाध्यक्ष, लहू खारगे को राज्य सहसचिव, तथा जिला सचिव पवन चिंचाने और जिला उपाध्यक्ष अंकुश कोकाटे को राज्य कमेटी सदस्य पद पर मनोनीत किया गया। इस अवसर पर बीड़ जिला कमेटी ने सभी नवनियुक्त राज्य पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को शुभकामनाएं दीं।

अधिवेशन का उद्घाटन एसएफआई के अखिल भारतीय महासचिव मयुख बिश्वास ने २ जून को किया। इस मौके पर स्वागताध्यक्ष प्रो. डॉ. प्रशांत विघे ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। शाम को

अधिवेशन के उपलक्ष्य में छात्र रैली और जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें डहाणू विधानसभा क्षेत्र के विधायक कॉमरेड विनोद निकोले, अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य महासचिव डॉ. अजित नवले, एसएफआई के नेता मयुख बिश्वास, सोमनाथ निर्मल, रोहिदास जाधव और श्याम शिंदे ने संबोधित किया।

प्रतिनिधि सत्र में राज्यभर से आए १८० प्रतिनिधियों ने पिछले ढाई वर्षों की शैक्षणिक, राजनीतिक और संगठनात्मक रिपोर्टों पर चर्चा की। अधिवेशन में शैक्षणिक सुधारों से जुड़े २४ प्रस्ताव भी पारित किए गए। इनमें शिक्षा के निजीकरण, व्यवसायीकरण, बढ़ती बेरोजगारी और अन्य मुद्दों के खिलाफ संघर्ष को तेज करने का संकल्प लिया गया। नवगठित राज्य कमेटी के प्रमुख पदाधिकारी इस प्रकार हैं:

राज्य अध्यक्ष: रोहिदास जाधव

राज्य सचिव: सोमनाथ निर्मल

राज्य उपाध्यक्ष: भास्कर म्हसे, मनिषा बल्लाळ, सत्यजित मस्के, विजय लोहबंदे, नवनाथ मोरे

राज्य सहसचिव: रामदास पी. एस., लहू खारगे, निशा साबळे, अशोक शेरकर

राज्य सचिव मंडल सदस्य: गीता दौडा, मीना आरसे, संदीप मरभळ

राज्य कमेटी सदस्य: संस्कृती गोडे, अक्षय घोडे, अंकिता धोडी, विरेंद्र दुमाडा, प्रतीक वेडगा, अंकुश कोकाटे, पवन चिंचाणे, अरुण मते, देवीलाल बागुल, कल्याणी माळी, रितेश चोपड़े, संदेश रामटेके, अनुजा सावरकर, विशाल शिंदे, अजय टोपले, नम्रता पटेल, लगन मंगला

मुख्य नारा: शिक्षा और रोजगार के लिए एक हों, शिक्षा क्षेत्र में लोकतंत्र को बचाएं

यह अधिवेशन छात्र एकता, सामाजिक बदलाव और शैक्षणिक अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उपळी में गौवंशीय मांस बरामद, आरोपी गिरफ्तार

स्थान: वडवणी, दिनांक ९ (प्रतिनिधि)

बीड जिले के वडवणी तालुका के उपळी गांव में पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर गौवंशीय मांस का अवैध भंडारण पकड़ा है। इस कार्रवाई में करीब ४०० किलो मांस जब्त किया गया है जिसकी कीमत लगभग ८० हजार रुपये बताई जा रही है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है।

वडवणी पुलिस थाने की सहायक पुलिस निरीक्षक वर्षा व्हगाडे को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के उपळी गांव में एक घर में गौवंशीय जानवर की अवैध रूप से हत्या कर मांस बेचा जा रहा है। सूचना मिलते ही उन्होंने पुलिस दल के साथ छापेमारी की।

छापे के दौरान मौके से ४०० किलो मांस, चाकू (सूरी) और लकड़ी की बल्ली (ओंडका) बरामद की गई। पुलिस ने ये सारा सामान जब्त कर लिया है और फेरोज सिकंदर कुरेशी नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

यह कार्रवाई सहायक पुलिस निरीक्षक वर्षा व्हगाडे, पुलिस उपनिरीक्षक राजू राठौड़, संदीप चव्हाण, पुलिस कर्मी विष्णु खरात, किरण इरमले, और वसंत करे की टीम ने मिलकर की।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गौवंशीय संरक्षण अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।

तलाब में डूबने से युवक की मौत; आष्टी तालुका की घटना

स्थान: आष्टी, दिनांक ९ (प्रतिनिधि)

आष्टी तालुका के मायंबा सावरगांव में सोमवार (दिनांक ९) दोपहर लगभग १ बजे एक युवक की तलाब में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब वह देवदर्शन के लिए क्षेत्र में आया हुआ था। अंभोरा पुलिस थाने में इस मामले को आकस्मिक मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया है।

मृत युवक का नाम गोकुल सावंत गडरी (उम्र २२ वर्ष) है, जो मेहुनबार, तालुका चाळीसगांव, जिला जलगांव का निवासी था। बताया गया कि जब उसने कुछ अन्य युवकों को तलाब में तैरते देखा तो वह भी तैरने के लिए पानी में उतर गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गोकुल सोमवार सुबह आष्टी तालुका स्थित मच्छिंद्रनाथ देवस्थान में दर्शन के लिए आया था। दर्शन के बाद वह अपने साथियों के साथ तलाब में तैरने गया। तैरते समय अचानक वह पानी में झटपटाने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जब उसके साथियों को उसकी हालत का पता चला, तो उन्होंने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर दौड़ पड़े और युवक को बचाने के लिए पानी में कूद गए। हालांकि, काफी प्रयासों के बावजूद गोकुल का कुछ पता नहीं चला। घटना की जानकारी मिलते ही आष्टी की तहसीलदार वैशाली पाटील मौके पर पहुंचीं। दोपहर ४ बजे तक सावरगांव के स्थानीय युवक गोकुल के शव की तलाश कर रहे थे, लेकिन तब तक उन्हें सफलता नहीं मिली थी।

ग्रामीण सड़कों के काम शुरू करने की मांग को लेकर बीड जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन

आ.संदीप क्षीरसागर पर दबाव की राजनीति से सड़क कार्यों के अटकने का आरोप

स्थान: बीड (प्रतिनिधि), दिनांक ९

बीड तालुका के ग्रामीण क्षेत्रों नालवंडी, पाली और अन्य जिल्हा परिषद क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण कार्य रोकने के आरोप को लेकर सोमवार (९ जून) सुबह ११ बजे बीड जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधानसभा सदस्य संदीप क्षीरसागर के दबाव के चलते ग्रामीण सड़कों के कार्यों में बाधा डाली जा रही है।

यह आंदोलन राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नालवंडी के सरपंच एड. राजेंद्र राऊत और भाजपा जिला सचिव शांतिनाथ डोरले के नेतृत्व में किया जा रहा है। आंदोलन में राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा नेता डॉ. योगेश क्षीरसागर, भूतपूर्व नगरसेवक अमर नाईकवाडे, महेश धांडे, भाजपा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ. लक्ष्मण जाधव, महात्मा फुले युवा दल के संस्थापक अध्यक्ष एड. सतीश शिंदे, भाऊसाहेब डावकर, युवक अध्यक्ष नंदकुमार कुटे, पंचायत समिति के पूर्व सदस्य उत्तरेश्वर सोनवणे, युवासेना जिला प्रमुख सुमित कोलपे, अरुण लांडे, प्रदीप गायकवाड़, सरपंच धनेश्वर खेत्रे, दत्ता जाधव, रोहित जाधव, सिद्धार्थ जाधव, राजाभाऊ नवले, लकी कंडेरे, राजू टाक, सुमंत राऊत, नामदेव म्हेत्रे, सखाराम राऊत, सचिन उनवणे सहित कई ग्रामीण नेता और नागरिक शामिल हुए। एड. राजेंद्र राऊत ने कहा कि आ. संदीप क्षीरसागर के दबाव के कारण सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अभियंता सड़कों के मार्कआउट देने से इनकार कर रहे हैं, जिससे पहले से स्वीकृत योजनाओं के बावजूद कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। उनका आरोप है कि जिन इलाकों से आ. क्षीरसागर को कम वोट मिले, वहां के काम जानबूझकर रोके जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि नालवंडी से मौज (वी.आर.क्र. २४३), कालेगांव हवेली से लमाण तांडा (वी.आर. ३५४), ओडीआर ५० से मानकुरवाडी (वी.आर. ३७), पाली से वरवटी (इजिमा १२७) जैसी कई सड़क परियोजनाएं जिला नियोजन समिति द्वारा वर्ष २०२४ में स्वीकृत की गई थीं और उनके कार्य प्रारंभ आदेश दिसंबर २०२४ में जारी हुए थे। बावजूद इसके, छह महीने बीत जाने पर भी विभाग द्वारा मार्कआउट नहीं दिया गया है।

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर बार-बार पत्र व्यवहार के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और कहा कि अब सड़क पर उतरना मजबूरी बन गया है। उन्होंने प्रशासन के रवैये की कड़ी निंदा करते हुए नाराजगी जाहिर की। धरना प्रदर्शन के दौरान जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रशासन और विधायक के खिलाफ विरोध दर्ज किया गया। अंत में, अपनी मांगों का ज्ञापन निवासी उपजिलाधिकारी शिवकुमार स्वामी को सौंपा गया। यदि १६ जून तक प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो जरुड फाटा पर रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा और जब तक जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते, तब तक रास्ता रोको आंदोलन जारी रहेगा-ऐसी चेतावनी भी एड. राजेंद्र राऊत ने दी।

चालू एसटी बस में लगी भीषण आग, चालक-वाहक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

स्थान: केज, दिनांक ९ जून (प्रतिनिधि)

सोमवार दोपहर करीब ३ बजे केज से कळंब की ओर जा रही यात्रियों से भरी एसटी बस (क्रमांक चक-११/इड-९३७५) में अचानक आग लग गई। यह घटना केज से साळेगांव के बीच चिंचोली पाटी के पास स्थित शेख फरीदबाबा दरगाह के समीप हुई। गनीमत रही कि बस चालक अनिल बारकुल और बस कंडक्टर भांगे की तेज़ सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई के कारण सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया।

कैसे हुआ हादसा:

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जैसे ही बस चिंचोली पाटी के पास पहुंची, बस के बोनट से धुआं उठने लगा और कुछ ही पलों में आग की लपटें उठने लगीं। चालक ने तुरंत बस को सड़क के किनारे रोका और कंडक्टर की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला।

=ह=फ आग बुझाने में देरी:

घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पूरी बस जलकर खाक हो चुकी थी।

मामूली रूप से घायल:

इस घटना में ३ से ४ यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया।

प्रशासन की कार्रवाई:

घटना के बाद परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, तकनीकी खराबी या वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी हो सकती है।

विशेष टिप्पणी: बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज़ से यह घटना एक गंभीर चेतावनी है। ऐसे हादसों से बचने के लिए एसटी विभाग को नियमित निरीक्षण, मशीनरी की जांच, और इमरजेंसी ट्रेनिंग अनिवार्य करनी चाहिए।

इस हादसे में चालक और कंडक्टर की सतर्कता ने यह सिद्ध किया कि प्रशिक्षण और त्वरित निर्णय किसी भी आपदा को टाल सकते हैं।

मुंबई लोकल हादसे पर मध्य रेलवे का बयान: फुटबोर्ड पर खड़े यात्रियों के कारण हुई दुर्घटना

रिपोर्ट: जमीर काज़ी । स्थान: मुंबई । दिनांक: ९ जून २०२५

दिवा और मुंब्रा स्टेशन के बीच सोमवार सुबह हुए दर्दनाक रेल हादसे में कई यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना को लेकर मध्य रेलवे प्रशासन ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए हादसे के लिए फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा कर रहे यात्रियों को जिम्मेदार ठहराया है।

रेलवे के अनुसार, यह हादसा सुबह लगभग ९:१० बजे हुआ, जब कसारा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जा रही लोकल ट्रेन से करीब आठ यात्री नीचे गिर गए। इस दुर्घटना की जानकारी सबसे पहले ट्रेन मैनेजर द्वारा दी गई, जिसके बाद एम्बुलेंस और रेलवे की आपातकालीन मेडिकल टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं।

घायलों को कळवा के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल और ठाणे सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस हादसे में चार यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि अन्य का इलाज जारी है। रेलवे प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्राथमिक जांच में सामने आए तथ्य:

रेलवे द्वारा जारी प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार, हादसे के समय कुछ यात्री ट्रेन के फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा कर रहे थे, जिससे वे असंतुलित होकर नीचे गिर गए। भीड़ के कारण ट्रेन के दरवाजे बंद नहीं किए जा सके, जिससे यह दर्दनाक घटना हुई।

अरे बाप ये जिंतूर में ३५ हजार घनमीटर अवैध मुरूम का उत्खनन

महसुल विभाग कुंभकर्ण की निंद में?

जिंतूर (प्रतिनिधी) तालुके के करवली शिवार में गट क्रं १२० के खेत जमिन में से बड़े पैमाने पर बेकायदा मुरुम का उत्खनन कर शासन का तब्बल २४ कोटी ७१ लाख रुपए का चुना लगानें का धक्का दायक मामला सामने आया है! इस प्रकरण में महसुल प्रशासन ने मुरुम का बेकायदा उत्खनन करने वाले पुर्व नगर सेवक इस्माइल सलीम शेख पर दंडात्मक नोटिस बजाई हैं! महसुल प्रशासन के चौकशी में ये मामला उजागर हुआ है! महसुल प्रशासन के अहवाल अनुसार दि २३ जानेवारी से २५ जानेवारी२०२५ ये कालावधी में ५० ट्रॅक्टर द्वारा मुरुम की बेकायदा वाहतूक की गई! संबंधित पुर्व नगर सेवक इस्माइल सलीम शेख के पास महसुल विभाग का मुरुम उत्खनन करने का कोई परवाना नहीं था! जिस के चलते महसुल प्रशासन का बडा आर्थिक नुकसान हुआ है!

पुर्व नगर सेवक इस्माइल शेख को २४ कोटी की नोटीस तो ४८ घंटे में खुलासा देने का आदेश

जिंतूर तालुके के करवली शिवार के गट क्रं १२० के खेत जमिन में से ३५, ४३६ ,०५, घनमीटर मुरुम का उत्खनन किया गया! ये प्रक्रिया तिन दिन तक ५० ट्रॅक्टर द्वारा चलाई गई! जिस का पता महसुल विभाग के संबंधित मंडल अधिकारी और तलाठी को कैसे दिखाई नहीं दी? ऐसा सवाल सुजान नागरिक उपस्थित कर रहे हैं! इस पुरे मामले में महसुल विभाग की भुमिका संशय के घेरे में दिखाई दे रही है! सखोल चौकशी की आवश्यकता है!

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com